



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 22 जनवरी, 1983/2 माघ, 1904

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 नवम्बर, 1981

सं० राज० 2-ए (3)-5/79—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (वर्ष 1954 का 6) की धारा 64 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (सामान्य) निर्धारण नियम, 1981 बनाने का विचार रखते हैं। इस नियमावली का प्रारूप इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित संलग्न है।

अतः जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 65 में विहित है, इस नियमावली का प्रारूप जन-साधारण की सूचनाार्थ प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति या समुदाय आदि को कोई आपत्ति हो या यदि वह कोई इस विषय में सुझाव देना चाहें, तो ऐसी आपत्ति या सुझाव अवर सचिव (राजस्व), हिमाचल

प्रदेश सरकार शिमला-171002 की सेवा में, दो मास की अवधि के अन्दर भेज दें। उक्त अवधि में प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा, अन्यथा दो मास के बाद यह नियमावली अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली जाएगी।

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/-
सचिव :

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (सामान्य) निर्धारण प्राव्य नियम, 1981

अध्याय I

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) ये नियम हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (सामान्य) निर्धारण नियम 1981 कहे जा सकते हैं।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) अभिप्रेत है;
- (ख) “स्वयं खेती करना” का वही अर्थ होगा जो कि इसे हिमाचल प्रदेश अभिवृत्ति तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का अधिनियम संख्यांक 8) में दिया गया है;
- (ग) “संपदा” अथवा “सम्बन्धित संपदाय” से अधिनियम में यथा परिभाषित कोई संपदा अथवा “संपदाओं का समूह” अभिप्रेत है, और जो कि अधिनियम के अधीन सामान्य निर्धारण के अध्याधीन किया जाना प्रस्तावित है;
- (घ) इन नियमों के प्रयोजन हेतु “राजस्व अधिकारी” से, धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ङ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (च) “अभिधारी” से हिमाचल प्रदेश अभिवृत्ति तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का अधिनियम संख्यांक 8) में यथा परिभाषित अभिधारी अभिप्रेत है; इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति आता है जो कि भूमि में मौखिक अथवा लिखित पट्टे अथवा संविदा के द्वारा अस्थायी हित रखता है; तथा
- (छ) इन नियमों में प्रयुक्त अन्य शब्द तथा पद जो यहां परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो कि क्रमशः उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय II

निर्धारण की मात्रा तथा शुद्ध परिसम्पत्तियों के धन मूल्य के आकलनों को तैयार करने का ढंग

3. निर्धारण का मात्रक.—धारा 52 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् राजस्व अधिकारी ऐसे क्षेत्र को जिनके लिए नई दरें निश्चित की जानी प्रस्तावित हैं, निर्धारण कृतों में विभक्त करेगा जो कि इन नियमों के प्रयोजन हेतु निर्धारण का मात्रक होगा।

4. भूमि का वर्गीकरण—(1) राजस्व अधिकारी निर्धारण के प्रयोजनों हेतु निर्धारण के अधीन समस्त भूमि को वर्गों में, उनमें दिखाई गई भूमि के प्रत्येक वर्ग को अन्तर्बिष्ट करते हुए निम्न रूप से विभक्त करेगा:—

(i) कृष्ट भूमि:

(क) बरानी	वर्षा पर निर्भर
(ख) सैलान	बाढ़ अस्त या जल द्वारा स्थायी रूप से गीली हुई भूमि
(ग) आली	उठाऊ व्यवस्था अथवा झरनों के प्रवाह द्वारा सिंचित
(घ) नहरी	नहरों द्वारा सिंचित
(ङ) वाही	कुओं द्वारा सिंचित
(च) कुहली	नहरों के जल द्वारा सिंचित
(छ) घासनी	घास उगाने के लिए आरक्षित भूमि

(ii) अकृष्ट भूमि:

(क) बंजर जदीद	ऐसी भूमि जो लगातार चार फसलों से बिना बोआई के रही हो
(ख) बंजर कदीम	ऐसी भूमि जो लगातार आठ फसलों से बिना बोआई के रही हो
(ग) गैर मुष्किन	ऐसी भूमि जो किसी कारण (कारणों) से कृषि योग्य न रही हो, जैसे सड़क, भवन, नदी, नहरों, तालाबों के अधीन भूमि अथवा इसी प्रकार की भूमि जो कि बंजर, रेतीली, रेत अथवा खड्ड, है।
(घ) खिल	कृषि योग्य भूमि जिसे अभी तक कृषि के लिए तैयार नहीं किया गया है।

(2) जब परिस्थितियाँ ऐसी हों तथा ऐसा किया जाना जनहित में समीचीन हो, तो राज्य सरकार अपने इस आशय के बारे में अधिसूचना द्वारा 15 दिन का नोटिस देने के उपरान्त, विशेष क्षेत्र के सम्बन्ध में उप-नियम (1) में निर्दिष्ट भूमि के वर्गीकरण में परिवर्तन कर सकती है।

5. शुद्ध परिसम्पत्तियों के आधार.—(1) राजस्व अधिकारी, प्रत्येक निर्धारण वृत्त में समाविष्ट यथा-स्थिति सम्बन्धित संपदा अथवा संपदाओं के वार्षिक कुल उत्पादन की शुद्ध परिसम्पत्तियों का आकलन निम्न आधार पर तैयार करेगा अथवा इसे तैयार करवाने की व्यवस्था करेगा:—

- (क) प्रत्येक वर्ग की भूमि पर प्रत्येक फसल का औसत क्षेत्रफल जिसके लिए अलग दरें निश्चित की जानी प्रस्तावित हैं, तथा
- (ख) उस भूमि में उगाई गई प्रत्येक फसल की प्रति एकड़ औसत पैदावार।

(2) जब भू-स्वामी व्यक्तिगत रूप में खेती करता हो तो सम्बन्धित संपदा अथवा संपदाओं की सकल वार्षिक उपज की परिसम्पत्तियों आकलन उपज के इकट्ठी करने के खर्च सहित कारीगरों अथवा परिचारकों के खर्चों की कटौती करने के उपरान्त प्राप्त हुआ शेष होगा और अन्य मामलों में अभिधारियों के भाग की भी कटौती करने के उपरान्त उपलब्ध शेष होगा।

व्याख्या.—

इस नियम के प्रयोजन हेतु,—

- (i) “औसत क्षेत्रफल आकलन” से सम्बन्धित पक्का सिंचित क्षेत्र होगा अर्थात् चुने गये वर्षों में किसी विशिष्ट क्षेत्र की, प्राकृतिक प्रकोपों के द्वारा हुई हानि अथवा क्षति की कटौती करने के पश्चात् प्राप्त पैदावार। ये वर्ष किसी वर्ष के चक्र अथवा अवधि से सम्बन्धित होंगे जिनमें कि कृषि उपज, कृषि क्षेत्र में होने वाली साधारण उतार चढ़ाव सम्बन्धी, उचित नमूना है;

- (ii) "औस्त पैदावार" का निर्धारण प्रयोगात्मक कटाई, भू-स्वामियों के खातों, जहाँ उपलब्ध हो, राजस्व अधिकारी द्वारा विश्वस्त व्यक्तियों से प्राप्त सूचना, उसके अपने प्रत्येक कृषि फार्मों द्वारा रखे गये खातों, यदि कोई हो, तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों में स्थित भू-भागों से अनुमानित उपज से किया जायेगा ;
- (iii) "कारीगरों अथवा परिचारकों को देय रकमें" वे होंगी जो उत्पादन में से गांव में कारीगरों अथवा परिचारकों को सहायता हेतु अथवा फसल कटाई अथवा कृषि उपकरण प्रदाय हेतु तथा मुरम्मत अथवा कृषि में सहायक किसी अन्य कार्य करने के, उसका कोई भाग दिया जाता है ;
- (iv) "अभिधारी का भाग" अभिकृति की शर्तों के अधीन रखी जाने वाली उपज का भाग होगा ।

6. समायोजन करना.—(1) संविदा के प्रतिकूल किसी बात की अनुपस्थिति में भू-राजस्व भू-स्वामी द्वारा देय होगा तथा जल व्यय यदि कोई हो अभिधारी द्वारा देय होगा । किसी अभिधारी द्वारा भू-राजस्व के कुछ भाग के अदा करने पर अथवा भू-स्वामी द्वारा पैटर्न दरों के अदा किये जाने की स्थिति में आकलन में यथास्थिति सम्बन्धित वृद्धि अथवा कटौती की जायेगी । भू-स्वामी द्वारा स्वयं खेती करने की स्थिति में परवर्ती खाते में से भी कटौती की जाएगी ।

(2) अभिधारी के माध्यम से खेती किये जाने की स्थिति में आकलन में से तत्स्थानी सीमा तक की अन्य कटौतियाँ निम्नलिखित परिस्थितियों में की जाएंगी:—

- (क) जब सिंचाई साधनों तक बांधों का अनुरक्षण भू-स्वामी द्वारा किया जाता है ।
- (ख) जहाँ बीज के सभी अथवा उसके किसी भाग का मूल्य तथा भूमि में प्रयुक्त खाद का मूल्य भू-स्वामी द्वारा वहन किया जाता है तथा इसका या तो उपज के वृहत भाग की रसीद द्वारा अथवा अन्य साधन द्वारा उससे प्रतिभार नहीं किया जाता है ।
- (ग) जहाँ भू-स्वामी अपने खर्च पर अपने अभिधारियों के प्रयोग के लिये उत्कृष्ट कृषि उपकरणों उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करता है तथा इनके प्रयोग के लिये, उपज का वृहत भाग लेकर अथवा अन्यथा किसी प्रकार का खर्च नहीं लेता ।
- (घ) जहाँ भू-स्वामी चारे का कोई भी भाग प्राप्त नहीं करता अथवा इसके कारण कोई अन्य वस्तु नहीं लता तथा अभिधारी को निम्न अनुमत देता है :—
 - (i) बैल की प्रत्येक जोड़ी के लिए चारा, उगाने के लिये विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा अन्य इसी आकार का कोई क्षेत्र, का रखना,
 - (ii) चारे के लिये कुछ हरी फसल का काटा जाना,
 - (iii) अपनी भूमि को अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य ढंग से चारा उगाने के लिये प्रयोग करना ।
- (ङ) जहाँ भू-स्वामी अपने उपज के भाग को इकट्ठा करने के लिये अपने खर्च पर किसी दत्त अभिकरण का नियोजन करता है ।
- (च) जहाँ भू-स्वामी कृषि प्रयोजनों के लिये अपने अभिधारियों को ब्याज रहित धन देता है :

परन्तु ऐसी कटौतियों पर अनुमत ब्याज दर उससे कम नहीं होगी जो कि राज्य सहकारी बैंक की निकटतम शाखा द्वारा उसके पास जमा ब्याज दर अनुमत है अथवा इसके दिये गए ऋण पर लिये गए ब्याज से अधिक है ।

7. आकलनों की उपज से धन मूल्य में परिवर्तन करना तथा प्रक्रिया के दौरान अपनाए जाने वाले मूल्य.—

- (1) उपज के आकलनों को तब धन मूल्य में परिवर्तित किया जाएगा । परिवर्तन के लिये अपनाए जाने वाले मूल्य उनके औसत मूल्य होंगे जो कि आने वाले बन्दोबस्त के दौरान कृषकों से फसलों पर

प्राप्त किये जाने हैं, परन्तु यह पर्याप्त लम्बी अवधि पर आधारित होगा और यह अनुमान लगाया जाएगा कि आगामी मूल्य की सीमा में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।

अकाल-वर्षों अथवा कठिन अभाव के दौरान गणनाओं से निकाल दिया जाएगा।

(2) इसके आगे प्रत्येक फसल के लिये अपनाया जाने वाला मूल्य उस मास में वर्तमान मूल्यों पर आधारित होगा जो कि कृषकों को सामान्यतः उनको उपज का निपटान करने से मिलता हो। यदि सम्बन्धित किसी संपदा अथवा संपदाओं के बारे में यह पाया जाए कि सर्वाधिक कृषक अपनी उपज को तगर मंडियों में ले जाकर वहां निपटान करते हैं तो ऐसी स्थिति में मण्डी तक ले जाने की टुलाई के खर्च तथा मंडी में अभिकर्ताओं, वजन करने वाले आदि को दी गई फीस, तथा अन्य यथा वास्तविक परम्परागत प्रचलित कटौतियों के लिये भत्ता दिया जाएगा।

टिप्पणी:—अपनाए जाने वाले मूल्यों का निर्धारण करते समय राजस्व अधिकारी उसके पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के साथ साथ निम्नलिखित की संवीक्षा करेगा :—

- (क) चयन किये गावों में दूकानदारों की बहियां ;
- (ख) क्षेत्रीय कानूनगो द्वारा वृत्त नोट बुक में इंदराज के लिखे प्रत्येक निर्धारण क्षेत्र के लिए रिपोर्ट किए गए फसल मूल्य ;
- (ग) राजपत्र में प्रकाशित फसल मूल्य ;
- (घ) मंडियों में मिलने वाले मूल्य ; तथा
- (ङ) बड़े भू-स्वामियों द्वारा अपनी उपज के लिये प्राप्त मूल्य।

8. नकद किरायों पर आधारित वास्तविक परिसम्पत्तियों के आकलन.—वास्तविक परिसम्पत्तियों का द्वितीय आकलन भी धारा 4 के खण्ड (2) में बनाए गए पूर्वानुमान पर सम्बन्धित सम्पदा अथवा सम्पदाओं में प्रचलित, अभिधारियों द्वारा, नकद देय किरायों, के आधार पर बनाया जाएगा। यह आकलन केवल वहां तैयार किया जाएगा जहां निम्नलिखित तत्व विद्यमान हैं:—

- (क) किसी वृत्त में प्रयाप्त बड़े पैमाने पर क्षेत्र भूमि की किराया लागत के आकलन के लिये मार्ग-दर्शन के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाली नकद किराया पद्धति का होना।
- (ख) मिट्टी तथा वर्ग के ऐसे विभेदीकरणों के राजस्व अभिलेखों में, जिनमें प्रायः किरायों के मूल्य का चिह्नित अन्तर संलग्न होता है, पहचान।

9. (1) ऐसे सभी किराये जो वास्तव में आर्थिक किराये नहीं हैं तथा भूमि की किसी किस्म के लिये दिये जाने वाले वास्तविक औस्त दर अथवा विद्यमान किराया दरों पर आधारित नहीं हैं, को राजस्व अधिकारी द्वारा असामान्य मानकर अपने परिकलनों के निकाल दिये जाएंगे। इस प्रयोजन के लिये निम्नलिखित किराये असामान्य समझे जाएंगे :—

- (क) मालिकाना शुल्क के कुछ अतिरिक्त भुगतान अथवा इसके बिना, भू-राजस्व के किराए जब तक कि भू-राजस्व अधिक तथा भूमि निकृष्ट न हो।
- (ख) सम्बन्धियों, मित्रों, अवलम्बितों अथवा धार्मिक कर्तव्यों को पालन करने वाले व्यक्तियों द्वारा अदा किया हुआ विशेषाधिकरण किराया।
- (ग) ईर्ष्या अथवा अस्थाई स्वरूप की विशेष स्थानीय अथवा व्यक्तिगत शर्तों द्वारा अनुचित रूप से गवित किराये अर्थात् ऐसे अत्यधिक किराए जो भूमि के वास्तविक किराया मूल्य अथवा किराया जिसमें अन्य तत्व जैसा कि बन्धक धन शामिल हो।

(2) राजस्व अधिकारी, निरीक्षण के अधीन आने वाले प्रत्येक गांव के नकद किरायों, यदि कोई हों, की सावधानी से परिनिरीक्षा करेगा। वह अपने आपको इस बात से संतुष्ट करेगा कि इन्हें उचित रूप से अभिलेख किया गया है तथा उसके पश्चात् वह यह निर्णय लेगा कि कौन से किराए को असामान्य मान कर निकाला जाएगा।

10. परिसम्पत्तियों के शुद्ध आकलन.—राजस्व अधिकारी, असामान्य किरायों के निकाले जाने के उपरान्त शेष रहे किरायों से, निम्न निर्देशों पर भू-स्वामी की शुद्ध परिसम्पत्तियों का आकलन तैयार करेगा :—

- (i) नियम 6 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे,
- (ii) बंजर भूमियों अथवा खराब फसल के लिये यदि आवश्यक हो, कटौतियां की जाएंगी :

परन्तु प्रत्येक अवस्था में की जाने वाली कटौती की राशि राजस्व अधिकारी द्वारा की गई स्थानीय जांच-पड़ताल के परिणामों पर आधारित होगी,

- (iii) किराए की उगाही में कमी के लिये कटौती की जाएगी जहां ऐसी कमी कुप्रबन्ध के कारण न हो ।

11. विविध आय.—यदि भू-स्वामी को किराया नकद अथवा जिन्स के रूप में लेते हुए भूमि से ऐसी कोई आय अथवा शुल्क प्राप्त होती हो तो इस अध्याय के अधीन बनाए गए आकलनों में हिसाब में नहीं लाई गई हो, तो ऐसी आय अथवा शुल्क की राशि को वास्तविक परिसम्पत्तियों में समाविष्ट किया जाएगा ।

12. वास्तविक शुद्ध परिसम्पत्तियों का आकलन.—इस अध्याय के अनुसार गणित परिसम्पत्तियों के आकलनों की तुलना की जाएगी तथा तब राजस्व अधिकारी निश्चित आकलन पर पहुंचेगा कि प्रत्येक सम्बन्धित सम्पदा व सम्पदाओं को ठीक शुद्ध परिसम्पत्तियां क्या हैं ।

अध्याय III

भू-राजस्व निर्धारण

13. पूर्वानुमान रिपोर्ट.—(1) किसी क्षेत्र के भू-राजस्व निर्धारण किये जाने से पूर्व निर्धारण के संभावित वित्तीय परिणामों के सम्बन्ध में पूर्वानुमान रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसमें यह दर्शाया जाएगा, चाहे वित्तीय कारणों अथवा अन्यथा के लिये पूर्वनिर्धारण वांछनीय है । रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ विषयों के बारे में विशिष्ट विवरण दिया जाएगा :—

- (क) विद्यमान निर्धारण, स्थानीय परिस्थितियों में इसके स्वरूप की उपयुक्तता तथा सम्पदाओं में इसके वितरण की न्याय संगति,
- (ख) खेती करने, जनसंख्या, सिंचाई साधनों, मंडियों तथा संचार साधनों में परिवर्तन,
- (ग) वर्षा,
- (घ) मूल्य, तथा
- (ङ) कोई अन्य कारण जो भू-भाग के सामान्य गुण को प्रभावित करता हो ।

(2) रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व सम्बन्धित क्षेत्र के प्रमुख कृषकों तथा भू-स्वामी के संगठनों से, यथा सम्भव विचार-विमर्श किया जाएगा तथा उन द्वारा दी गई राय तथा उस पर सम्बन्धित राजस्व अधिकारी की प्रतिक्रिया का उल्लेख रिपोर्ट में किया जाएगा ।

14. (1) प्रस्तावों का प्रकाशन.—राजस्व अधिकारी वन्दोबस्त कार्यों के आरम्भ होने के पश्चात् यथाशीघ्र क्रमशः नियम 3, 4, 5 तथा 7 के उपबन्धों के अनुसार निर्धारण वृत्तों के विषय में भूमि की किस्म, चुने गए वर्षों तथा अपनाए जाने वाले मूल्यों के बारे में अपने प्रस्तावों को तैयार करेगा ।

(2) राजस्व अधिकारी अपने प्रस्तावों का सारांश देवनागरी लिपि में हिन्दी में तैयार करेगा । इस सारांश को हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा । इस सारांश की मुद्रित प्रतियां डाक द्वारा सभी विधायकों, भू-स्वामियों के संगठनों, ग्राम पंचायत प्रधानों, लम्बरदारों, पंचायत समितियों तथा जिला-परिषदों के अशासकीय सदस्यों, जो कि सम्बन्धित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, को उनकी आपत्तियों तथा

मुझावों को मंगवाने के लिए भेजी जाएगी। प्रतियों को भेजे जाने की तिथि से 30 दिन की अवधि दी जायेगी जिसमें वह उप-नियम (1) के अधीन निदिष्ट सभी आवश्यक विषयों के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारी को आपत्तियां तथा मुझाव भेज सकते हैं।

(3) राजस्व अधिकारी ऐसी आपत्तियां आदि पर विचार करेगा तथा उन पर अपनी राय देने के पश्चात्, उन्हें अपने मुझावों सहित वित्त आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार के आदेशों के लिए भेजेगा।

15. संपदाओं का निरीक्षण.—धारा 54 की उप-धारा (10) के अधीन विहित रिपोर्ट तैयार करने में पूर्व राजस्व अधिकारी प्रत्येक संपदा का विशेष निरीक्षण करेगा तथा रिपोर्ट पर निरीक्षण टिप्पणी को अभिलेख करेगा।

16. निर्धारण रिपोर्ट का प्रारूप.—राज्य सरकार के आदेशों की प्राप्ति पर, राजस्व अधिकारी, विद्यमान निर्धारण, नियम 12 के अधीन निर्धारित वास्तविक शुद्ध परिसम्पत्ति तथा अन्य सभी सम्बद्ध कारणों को ध्यान में रख कर प्रत्येक निर्धारण वृत्त के बारे में भविष्य के निर्धारण के सम्बन्ध में उस द्वारा दिये गये मुझावों को अन्तर्विष्ट करते हुए प्रारूप-रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट में प्रत्येक निर्धारण वृत्त के सम्बन्ध में अन्य बातों के साथ साथ निम्न बातें भी अन्तर्विष्ट होंगी :—

- (क) उस द्वारा परिकलित वास्तविक शुद्ध परिसम्पत्तियों का मूल्य,
- (ख) पुनः निर्धारण, जिसको वह प्रस्तावित करता है, तथा
- (ग) विवर्णित दरें, जिन पर वह इसे जमीन या फसल की विभिन्न किस्मों के लिए वितरित करना प्रस्तावित करता है।

17. प्रकाशित की जाने वाली निर्धारण रिपोर्ट.—(1) प्रारूप रिपोर्ट तैयार हो जाने पर राजस्व अधिकारी, हिन्दी में देवनागरी लिपि में संक्षिप्त सारांश तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा :—

- (क) मुख्य तिथि, जिस पर वास्तविक परिसम्पत्तियों का आकलन आधारित है, अर्थात् ग्रहण की गई फसल की दर, नकद तथा अन्य तरीके से किराये की दर, कुल औस्त कृष्ट तथा पक्का सिंचित क्षेत्र, अनुमत कटौतियां अथवा कृषि पर खर्च, परिचारकों का खर्च आदि, तथा उस भूमि का मूल्य जो बिक्री तथा रहन द्वारा निपटाई गई है;
- (ख) सामान्य तर्क जिन पर पड़ाव तथा कुल वास्तविक प्रस्तावित निर्धारण की राशि आधारित है अर्थात् सिंचाई द्वारा साधनों में वृद्धि, कृषि में विस्तार, मूल्यों में वृद्धि, विविध आय इत्यादि; तथा
- (ग) गांव निर्धारण करते समय उसे ग्रहण करने के लिये ऐसे संक्षिप्त स्पष्टीकरणों सहित जैसे, आवश्यक समझा जाये कुल निर्धारण तथा औस्त प्रस्तावित राजस्व दरें, जिसमें स्पष्ट उपबन्ध हो कि इस चीज का कोई प्रतिभू नहीं है, कि किसी विशेष सम्पदा का निर्धारण ठीक प्रस्तावित दरों पर किया जायेगा तथा उसे राजपत्र में प्रकाशित करवाया जायेगा।

(2) इस सारांश की प्रतियां, सम्बन्धित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी विधायकों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, लम्बरदारों, भू-स्वामियों के संगठनों तथा पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के अशासकीय सदस्यों को भी डाक द्वारा भेजी जायेगी।

(3) डाक द्वारा प्रतियां भेजने की तिथि से तीस दिन की अवधि अनुमत होगी जिसमें कोई भी राजस्व भुगतानकर्ता का समूह अथवा अभिधारी राजस्व अधिकारी के पास प्रस्तावित निर्धारण के लिए अपने मुझाव तथा आपत्तियां दे सकता है।

(4) ऐसे सभी मुझावों तथा आपत्तियों आदि पर राजस्व अधिकारी द्वारा अन्तिम रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व विचार किया जायेगा।

18. अन्तिम रिपोर्ट.—राजस्व अधिकारी प्राप्त सुझावों तथा आपत्तियों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, अन्तिम रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे धारा 53 की उप-धारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित, स्वीकृति के लिए वित्तीय आयुक्त के माध्यम से निम्नलिखित सहित सरकार को भेजेगा :—

- (क) सुझाव अथवा आपत्तियों का, यदि कोई प्राप्त हो, उन पर उसके विचारों सहित, कारणों सहित सूक्ष्म रूप से पुष्टिकरण के साथ, यथास्थिति सारांश, तथा
- (ख) नियम 17 के अधीन प्रकाशित सारांश सहित, नियम 16 के अधीन तैयार की गई प्रारूप रिपोर्ट की एक प्रति ।

19. रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा तथा ऐसा विचार करने के पश्चात् वह किसी ढंग से अथवा इसके बिना तीन प्रतिशत मात्रा तक बिसामान्यता सहित निर्धारण प्रस्तावों का अनुमोदन कर सकती है ।

20. विशिष्ट संस्थाओं का निर्धारण.—धारा 54 की उप-धारा (3) के उपबन्धों के अध्याधीन, प्रत्येक सम्पत्ति का निर्धारण परिस्थितियों के अनुसार नियत किया जायेगा ।

21. प्रगतिशील निर्धारण.—यदि आवश्यक हो, तो विशिष्ट संपदाओं पर प्रगतिशील रूप में संशोधित मांग अधिरोपित कर के भू-राजस्व की भारी वृद्धि को कम किया जा सकता है, अर्थात् बढ़ी हुई मांग का कुछ भाग पांच से दस वर्ष की अवधि के लिए अस्थापित किया जायेगा ।

22. जोतों पर निर्धारण का वितरण.—(1) किसी संपदा की अनेक जोतों पर नियम निर्धारण के वितरण करने या उसका संशोधन करने से पूर्व राजस्व अधिकारी, पूर्ववर्ती वितरण प्रथा की जाँच-पड़ताल करेगा तथा वितरण के नये ढंग का निर्णय करते समय जहाँ तक व्यवहार्य तथा न्यायसंगत हो उस प्रथा तथा भू-स्वामियों की इच्छाओं को ध्यान में रखेगा ।

(2) (क) राजस्व अधिकारी पिछली वितरण प्रथा को वर्णित करके एक आदेश देगा तथा ऐसा ढंग जिससे नया वितरण करना हो, बतायेगा तथा निर्देश देगा कि निम्नलिखित को दर्शाते हुए नये वितरण का अभिलेख तैयार किया जाये :—

- (1) जोत की कम संख्या;
- (2) जोत पर भू-राजस्व के लिए (विवरण सहित) दायी भू-स्वामी ;
- (3) ऐसे व्योरे सहित, जो वितरण के लिए आवश्यक हो, जोत का क्षेत्र;
- (4) माप की दर, जिसके द्वारा नया वितरण किया गया है;
- (5) पुराने वितरण द्वारा नया वितरण किया गया है;
- (6) पिछले वितरण द्वारा प्रत्येक जोत द्वारा देय भू-राजस्व पर प्रतिशत के हिसाब से प्रभावित कर तथा उपकर;
- (7) नये वितरण द्वारा प्रत्येक जोत के लिए वसूल की गई राशि; तथा
- (8) नये वितरण के प्रत्येक जोत द्वारा देय भू-राजस्व पर प्रतिशत के हिसाब के प्रभावित कर तथा उपकर ।

(ख) जहाँ अभिधारी का किराया सारा है अथवा उसके भू-राजस्व का कोई भाग, धन, किस्म अथवा सेवा जोड़ सहित अथवा उसके बिना है, अभिवृत्ति अथवा कार्यवाहियों का परिणाम जो कि हिमाचल प्रदेश अभिवृत्ति निधि भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) के अधीन, अभिधारी का नाम, प्रविष्टियों (2) तथा (3) के बीच अंकित करके, दर्शाते हुए अतिरिक्त प्रविष्टि द्वारा किया गया है तो उन्हें भू-स्वामी के जोत के अधीन जिसका अभिवृत्ति तक भाग है, दर्शाया जायेगा ।

(3) इस तरह तैयार किये गये अभिलेख का प्रचार, उसकी एक प्रति सम्पदा के मुख्य भू-स्वामी को देकर तथा उसकी अन्य प्रति को सम्पदा में उसके या समीप सुस्पष्ट स्थान पर चिपका कर किया जायेगा । एक प्रति पट्टारी को भी दी जायेगी ।

(4) यदि निर्धारण, प्रत्येक वर्ष या फसल के परिणाम के अनुसार प्रभाय दरों के रूप में हो, तो सहायक कुल्लुक्टर जिसे राजस्व अधिकारी से धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन आदेश द्वारा इस कार्य को सौंपा गया हो, प्रत्येक वर्ष या फसल के लिए, यथास्थिति, प्रत्येक जोत के लिए प्रभाय राशि का उप-नियम (2) में विवरण दिखाकर प्रविष्टियों (5) तथा (6) के सिवाय अभिलेख तैयार करवायेगा तथा उप-नियम (3) में विहित ढंग से उसका प्रचार करेगा।

अध्याय IV

सुधार के लिए निर्धारण में छूट देने हेतु सिद्धान्त

23. वृद्धि से हुए सुधार द्वारा लाभान्वित हुई भूमि के लिए छूट.—(1) इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व जब सिंचाई के लिए प्राइवेट खर्च पर या सरकार से प्राप्त ऋण की सहायता से चिनाई कुआं बनाया जाए, तो कुएं से लाभान्वित होने वाली भूमि भी उसी वृद्धि या अतिरिक्त भू-राजस्व निर्धारण से, कुएं के बने रहने की अवधि से ऐसी अवधि की समाप्ति तक जैसे कि पूर्व समझौते के अनुसार स्वीकृत हो, जो उस फसल से मानी जायेगी जिसके लिए कुएं का पहली बार प्रयोग किया गया हो, से छूट प्राप्त होगी। इस नियम के प्रयोजन के लिए न्यूनतम छूट की अवधि बीस वर्ष होगी, परन्तु किसी अन्य स्थिति में जहां यह दर्शाया गया हो कि ऐसी अवधि भू-स्वामी के लिए कुएं से देय अतिरिक्त वास्तविक परिसम्पत्तियों में से कुएं के दो गुना खर्च का प्रतिशोधन करने के लिए पर्याप्त है, तो ऐसी अवधि को 40 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझी जाए। यदि किसी स्थिति में राजस्व अधिकारी, 40 वर्ष तक की अवधि के लिए छूट देने के लिए मना करता है, तो अप्रकृत पार्टी को वित्तायुक्त के पास अपील करने का अधिकार होगा।

(2) जहां कुएं का प्रयोग किया जा रहा हो, अथवा जीर्णोद्धार के कारण प्रयोग नहीं किया जा रहा हो, यदि सिंचाई के लिए मुरम्मत की जाती है, तो कुएं की मुरम्मत पर आए खर्च तथा उप-नियम (1) में वर्णित सिद्धान्त के सम्बन्ध में ऐसी अवधि के लिए, जो उस उप-नियम में उल्लिखित अवधि से अधिक न हो, जैसा कि छूट देने वाला अधिकारी उचित समझे, उप-नियम (1) के बराबर खर्च में छूट दी जा सकती है।

(3) जब सिंचाई के लिए प्राइवेट खर्च पर या सरकार से प्राप्त ऋण की सहायता से ट्यूब वेल निर्मित किया जाता है, तो ऐसी भूमि जो ट्यूबवेल से लाभान्वित होती हो, उसे राजस्व की वृद्धि या अतिरिक्त निर्धारण के दायित्व से, जो कि कुएं के बने रहने पर देय, इतनी अवधि की समाप्ति तक भार से मुक्त होगी जैसे वित्त आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिए भू-स्वामी को विद्यमान कुएं से प्राप्त अतिरिक्त वास्तविक परिसम्पत्तियों में से दोगुना खर्च अदा करने के लिए पर्याप्त समझी जाये। इस नियम के लिए छूट की अवधि 30 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 40 वर्ष होगी।

(4) उप-नियमों (1) से (3) में उल्लिखित छूट की अवधि के दौरान कुएं अथवा ट्यूबवेल से सिंचित भूमि का भू-राजस्व निर्धारण की गई राशि से अधिक नहीं होगा, यदि कोई नया कुआं नहीं बनाया गया होता या किसी पुराने कुएं की मुरम्मत नहीं की गई होती तो विशेषतः छूट की अवधि के दौरान कुएं पर कोई निश्चित एक मुश्त राशि का निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(5) उन भू-भागों में जहां असिंचित होने से यदि व्यवहारिक रूप से भूमि का निर्धारण नहीं हुआ हो, तो नदी की बाढ़ या नहर के पानी की पहुंच से बाहर की कुएं से सिंचित भूमि पर कुल नियत निर्धारण अर्थात् चाही खालिस छूट के दौरान माफ किया जायेगा। चाही सैराब, चाही नहरी भूमियों की स्थिति में छूट के दौरान अधिरोपित निर्धारण दरें निम्न प्रकार से होंगी:—

(क) जहां कुएं से सिंचित भूमि, नदी की बाढ़ के भीतर स्थित हो, तो यथास्थिति, निर्धारित अथवा अस्थिर, सैलाब दर या दरें, नियत या अस्थिर यथास्थिति तत्समय स्वीकृति की गई हो, तथा

(ख) जहां भूमि नहरी पानी की पहुंच के भीतर हो, तो यथास्थिति नियत या अस्थिर नहरी खालिस दर या दरें यथास्थिति तत्समय के लिए स्वीकृत की गई हों:

परन्तु जहां उपर्युक्त उल्लिखित भू-भागों में यदि कुएं से सिंचित भूमियों पर कोई नियत निर्धारण नहीं किया गया हो, तो उपर्युक्त सैलाब या नहरी खालिस दर या दरों के अतिरिक्त कोई दर नहीं ली जायेगी।

(6) कुओं अथवा ट्यूबवैलों के अतिरिक्त, डैमों, जैसा कि जलाशयों, छोटी नदियों, सघु नहरों या सहायक नहरों, जिन्हें सिंचाई के लिए प्राईवेट खर्च पर अथवा सरकार से प्राप्त ऋण की सहायता से निर्मित किया गया हो अथवा जिनकी मुरम्मत की गई हो तो उनके लिए भी छूट उप-नियम (1) तथा (2) के अधीन कुओं के लिए दी गई छूट की तरह प्रदान की जायेगी।

प्रत्येक मामले में ऐसी छूटें राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी, परन्तु वित्त आयुक्त की स्वीकृति के बिना दस वर्ष की अवधि से अधिक तथा राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना बीस वर्ष की अवधि से अधिक छूट नहीं दी जायेगी।

(7) पूर्ववर्ती उप-नियमों में विनिर्दिष्ट छूट की अवधियां, पर्याप्त कारणों के साथ राज्य सरकार की स्वीकृति से बढ़ाई जा सकती हैं।

24. कुएं प्रयोग के योग्य न रहने पर राजस्व में माफी.—(1) सिंचाई द्वारा बने कुएं या ट्यूबवैल से सिंचित भूमि के निर्धारण में माफी, कुएं से की गई सिंचाई से हुए लाभों के आधार पर दी जाएगी, जब—

(क) कुआं प्रयोग के उपयुक्त न रहे; या

(ख) इससे सिंचाई का स्थान नहरी सिंचाई ने ले लिया है, नहरी लाभ राजस्व अथवा स्वामी दर अधिरोपित किये गये हों।

(2) इसी प्रकार की माफी दी जा सकती है, यदि कुआं प्रयोग के लिये ठीक हो, तथा उसे निरन्तर चार फसलों के लिये प्रयोग में न लाया गया हो परन्तु किसी भी प्रकार की माफी नहीं दी जाएगी यदि कुएं का अनुपयोग :—

(क) (अनुपयोग) कृषि कर्म की सामान्य अवधि में होता है, कुएं का प्रयोग केवल सूखे में किया जाना अभिप्रेत हो; तथा

(ख) (अनुपयोग) नहर द्वारा सिंचाई करने पर हुआ हो, तथा नहर के प्रयोग का राजस्व अथवा मालिकी दर अधिरोपित किए गए हों।

स्पष्टीकरण.—कुएं द्वारा की गई सिंचाई के लाभों पर आधारित राजस्व सामान्यतः निम्न अनुसार माना जाएगा :—

(i) जहां बिना कुएं की दर के अतिरिक्त कुएं के निर्धारण के वितरण पर एक मुश्त राशि अधिरोपित की गई हो, वहां ऐसी एक मुश्त राशि,

(ii) जहां बिना कुएं की दर सम्मिलित किये, निर्धारण के वितरण पर एक मुश्त अधिरोपित की गई हो तो बिना कुएं की दर के बराबर राशि कटौती करके एक मुश्त राशि, तथा

(iii) जहां निर्धारण का वितरण भूमि दरों पर हो, तो सींचित क्षेत्र के वास्तविक निर्धारण तथा उस क्षेत्र, यदि यह सींचित नहीं हो, पर निर्धारित राशि में अन्तर।

25. कुओं के लिए बन्दोबस्त के समय नीयत की जाने वाली छूट अवधि.—जब बन्दोबस्त कार्य चल रहा हो, तो राजस्व अधिकारी वित्त आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार से प्रत्येक निर्धारण वृत्त के लिए ट्यूबवैल कुओं के अतिरिक्त अन्य कुओं के लिये छूट अवधि सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करेगा।

26. बन्दोबस्त के समय छूट-प्रमाण-पत्र का प्रदान करना.—प्रत्येक मामले में जिसमें राजस्व अधिकारी छूट प्रदान करता है, वह भू-स्वामी को कुएं अथवा अन्य कार्य जिसके लिये छूट दी गई हो, कुएं के निर्माण तथा मुरम्मत की दर, जिस अवधि तक छूट रहेगी, भूमि जिसका अन्यथा सींचित दरों पर निर्धारण किया गया हो, तथा अतिरिक्त मांग जिसकी छूट की अवधि के अन्त में अधिरोपित किया जाना हो, का उल्लेख करते हुए छूट का प्रमाण-पत्र देगा। यदि भूमि अस्थिर निर्धारण के अधीन है, तो प्रमाण-पत्रों में इसके बाद यह स्पष्ट किया जायेगा कि छूट उस प्रणाली के अधीन होगी जैसे कि भू-भाग के लिये स्वीकृति की गई हो।

27. अन्य समय पर प्रमाण-पत्र देना.—जब बन्दोबस्त के दौरान किसी कुएँ, ट्यूबवेल या अन्य कार्य का ऐसी परिस्थितियों में, जो स्वामी को मीचित दरों के निर्धारण में छूट के लिये अधिकृत करती है, का निर्माण या मुरम्मत की जा रही हो, तब राजस्व अधिकारी विशेष जांच-पड़ताल करेगा तथा नियम 23 के उपबन्ध के अनुसार छूट का प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा। यदि छूट तुरन्त लागू होनी हो तो जहाँ तक हो सके, प्रमाण-पत्र नियम 26 में उल्लिखित सभी विवरणों को प्रकट करेगा तथा इसके अतिरिक्त माफ की जाने वाली विद्यमान राजस्व राशि को स्पष्टतया दिखायेगा, परन्तु यदि अगले निर्धारण संशोधन तक प्रवृत्त नहीं हो, तो कोई भी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है, जब कि उस कार्य का स्वामी लिखित रूप में प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन नहीं करता। ऐसे मामलों में अनुदान अथवा छूट राशि के अध्याधीन क्षेत्र के लिये कोई प्रविष्टि नहीं की जायेगी।

28. कृषि योग्य बनाई गई बंजर भूमि पर छूट.—(1) जब कोई भू-स्वामी बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिये मूल खर्च की क्षतिपूर्ति करने के लिये कृषि योग्य बनाई गई बंजर भूमि के निर्धारण से छूट चाहता हो, तो वह काम आरम्भ करने से पूर्व बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाई जाने वाली भूमि का विवरण देकर इसे कृषि योग्य बनाने के लिये आई कठिनाइयाँ तथा भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि के लिये राज्य सरकार को आवेदन करेगा सरकार ऐसी जांच-पड़ताल करने के उपरान्त जैसे वह आवश्यक समझे इस बात का निर्णय लेगी कि क्या कोई छूट दी जाएगी।

(2) यदि आवेदित छूट स्वीकृत कर दी जाती है तो छूट दी जाने वाली अधिकतम अवधि कृषि योग्य भूमि बनाने का कार्य बन्द होने पर नियत की जाएगी, राज्य सरकार कृषि योग्य भूमि बनाने तथा कृषि योग्य बनाए क्षेत्र पर खर्च की गई वास्तविक राशि सत्यापन के उपरान्त तथा ऐसी अवधि के लिये भू-राजस्व के निर्धारण से, पहले नियत की गई अधिकतम सीमा के अध्याधीन जो कि कृषि योग्य बनाने के कार्य पर हुई खर्च राशि के दुगुने तक पर्याप्त हो, छूट देगी।

अध्याय V

निर्धारण की घोषणा करने का ढंग

29. प्रत्येक सम्पदा के लिये निर्धारण आदेश.—राजस्व अधिकारी, राज्य सरकार से अपने निर्धारण प्रस्तावों पर आदेश प्राप्त करने पर प्रत्येक भू-सम्पदा पर उचित निर्धारण करने के आदेश तैयार करेगा।

30. निर्धारण की घोषणा.—(1) प्रत्येक सम्पदा पर अधिरोपित निर्धारण की घोषणा करने के प्रयोजन हेतु मुखियों तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट स्थान तथा तिथि पर उपस्थित होने के लिये उन्हें बुलाने की सूचना दी जायेगी। राजस्व अधिकारी ऐसी तिथि तथा ऐसे स्थान पर निर्धारण की घोषणा करेगा।

(2) प्रत्येक सम्पदा के मुखिया को एक ज्ञापन दिया जायेगा जिसमें सम्पदा का आगामी निर्धारण, तथा कोई अतिरिक्त विशिष्टियाँ जो अवश्य समझी जाएं दिखाई गई हों।

(3) जिस फसल से नई मांग लागू होगी, उसकी सूचना मुखिया तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों को दी जायेगी तथा मुखिया को दिए गए ज्ञापन में लिखी जायेगी।

अध्याय VI

भू-राजस्व की दर की गणना करने का ढंग

31. आयतन की गणना.—(1) उन निर्धारण वृत्तों में जिनमें अन्तिम पूर्ववर्ती निर्धारण पर नियत निर्धारण अधिरोपित किया गया था ऐसे निर्धारण का आयतन दर, कृष्ट भूमि पर राजस्व अधिकारी द्वारा जिसने कृष्ट क्षेत्र द्वारा निर्धारण का प्रयोजन हेतु जैसा कि उससे निश्चय किया गया, यथा अन्तिम रूप में अधिरोपित कुल निर्धारण को विभाजन करने पर प्राप्त दर होगा।

(2) जिन निर्धारण वृत्तों में अन्तिम पूर्ववर्ती निर्धारण पर अस्थिर निर्धारण अधिरोपित किया था, फसलों को ओसत जो ऐसे निर्धारण पर वास्तविक परिसम्पत्तियों का आधार होती है को स्वीकृत अन्तिम दरों से गुणा

किया जायेगा इस तरह प्राप्त होने वाले आंकड़ों को राजस्व अधिकारी द्वारा जिसने निर्धारण अधिरोपित किया है, निर्धारण के प्रयोजन यथा सुनिश्चित कृष्ट क्षेत्र द्वारा विभाजन किया जायेगा और परिणाम अन्तिम पूर्ववर्ती निर्धारण दर होगा।

(3) उन निर्धारण वृत्तों में जिनमें अन्तिम पूर्ववर्ती निर्धारण पर अधिरोपित निर्धारण अंशतः नियत तथा अंशतः अस्थिर था, फसल फार्म जिसका वास्तविक परिसम्पत्तियों अथवा ऐसे अनुमानित निर्धारण के अध्याधीन है, को अस्थिर निर्धारण के लिये स्वीकृत अन्तिम दरों द्वारा गुणा किया जाएगा।

(4) संशोधित निर्धारण के प्रयोजन हेतु कृष्ट क्षेत्र पर आयतन दर इस नियम के उप-नियम (1), (2) तथा (3) में ऐसी प्रणालियों द्वारा जो पूर्ण निर्धारण पर राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित कृष्ट क्षेत्र को प्रयोज्य निर्धारण के अधीन वृत्तों में परिस्थितियों यथा प्रयोज्य हो, आवश्यक परिवर्तन सहित निर्धारित की जायेगी।

32. निरसत तथा अपवाद.—(1) पंजाब भू-राजस्व निर्धारण नियम, 1929, जो हिमाचल प्रदेश में प्रयोज्य तथा लागू हैं, को एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नियमों के निरसित होते हुए भी, निरसित नियमों के अधीन की गई कोई भी बात या कार्यवाही, अधिसूचना उद्घोषणा आदेश अथवा जारी किए गए निदेश या अधिसूचना इनके निरसित नियमों के अधीन बनाई गई परियोजनायें, इन नियमों के स्थानीय उपबन्धों के अध्याधीन यथास्थिति की गई, जारी की गई, अथवा बनाई गई समझी जायेगी और तब तक लागू रहेगी जब तक कि अन्यथा निर्देशित न हो अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा की गई किसी बात अथवा की गई कार्यवाही द्वारा अधिक्रमण न किया गया हो।

THE DRAFT HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (GENERAL) ASSESSMENT RULES, 1981

CHAPTER I

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Land Revenue (General) Assessment Rules, 1981.

(2) These shall come into force at once.

2. *Definition.*—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954);
- (b) "to cultivate personally" has the meaning assigned to it in the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (Act No. 8 of 1974);
- (c) "estate" or "estates concerns" means an "estate" or "group of estates" as defined in the Act, and proposed to be subjected to general assessment under the Act;
- (d) "Revenue Officer" for the purposes of these Rules means a Revenue Officer authorised by the State Government for making assessment under sub-section (1) of section 53;
- (e) "section" means a section of the Act;
- (f) "tenant" means a tenant as defined in the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (8 of 1974) and includes a person having any temporary interest in the land of the landowner by way of a verbal or written lease or contract; and
- (g) all other words and expressions used in these rules but not defined herein, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

UNIT OF ASSESSMENT AND MANNER OF PREPARATION OF ESTIMATES OF MONEY VALUE OF NET ASSETS

3. *Unit of assessment.*—The Revenue Officer shall, as soon as may be after a notification under sub-section (2) of section 52 is issued, divide the area for which new rates are proposed

to be framed, into assessment circles, which shall be the unit of assessment for the purposes of these rules.

4. Classification of Land.—(1) The Revenue Officer shall, for the purposes of assessment, divide the entire land under assessment in the following groups, each containing the classes of land shown thereunder:—

(I) Cultivated land:

- (a) Barani: dependent on rainfall;
- (b) Sailab: flooded or kept permanently moist by water;
- (c) abi: watered by lift system or by flow from springs;
- (d) nehri: irrigated from canals;
- (e) chahi: watered from wells
- (f) kuhli: irrigated by water channel;
- (g) ghasani: land reserved for growing grass; and

(II) Uncultivated land:

- (a) Banjar jadid: land which has remained unsown for four successive harvests;
- (b) banjar quadim: land which has remained unsown for eight successive harvests;
- (c) gair mumkin: land which has for some reason(s) become unculturable, such as land under roads, buildings, streams, canals, tanks or the like or the land which is barren, sand or revine;
- (d) Khil: Cultivable land which has not yet been broken up.

(2) Whenever the circumstances so warrant and it is expedient to do so in the public interest, the State Government after giving by notification 15 days notice of its intention so to do may by notification alter the classification of the lands as given in sub-rule (1) in regard to a particular area.

5. The basis of net assets.—(1) The Revenue Officer shall prepare or cause to be prepared an estimate of net assets of annual gross produce of the estate or the estates concerned, as the case may be, comprised in each assessment circle, on the following basis:—

- (a) the average acreage of each crop on each class of land, for which it is proposed to frame separate rates; and
- (b) the average yield per acre of each crop grown thereon.

(2) The estimate of the net assets of the annual gross produce of the estate or estates concerned when the landowner cultivates the land personally, shall be the result obtained after deducting the dues of artisans and/or menials along with collection expenses from the produce, and in other cases, shall be the result obtained by deducting the tenants share also.

Explanation.—For the purposes of this rule,

(i) 'average acreage' in relation to an estimate shall be the average matured area i.e. average yield from a particular area obtained after deducting the percentage of loss or damage caused due to natural calamities, of the selected years. These years shall be the cycle or period of year of which the harvest are a fair sample of the ordinary fluctuation characteristic of the agriculture of the tract;

(ii) 'average yield' shall be assessed on the result of experimental cutting, accounts of the landowners where obtainable, information gathered from the trustworthy persons by the revenue officer, his own observations, accounts maintained by agricultural farms, if any, and the yields assumed for similar tracts elsewhere;

- (iii) 'dues of artisans or menials' shall be the portion of the produce paid to artisans or menials for help in village or for harvesting or for supply and repair of agricultural implements or for any other work subsidiary to agriculture; and
- (iv) 'tenant's share' shall be the portion of produce retainable by the tenant under the terms or tenancy.

6. *Adjustment to be made.*—(1) In the absence of a contract to the contrary, land revenue shall be payable by a landowner, and water rates by a tenant, if any. In case a tenant pays a certain proportion of land revenue or a landowner pays a certain portion of the water rates, a corresponding addition to or as the case may be deduction from, the estimate shall be made. The deduction on the latter account shall also be made in case, the landowner cultivates the land personally.

(2) The other deductions of the corresponding extent from the estimates shall be made in the following circumstances, in case the land is cultivated through a tenant:—

- (a) when means of irrigation and embankments are maintained by landowner;
- (b) where the cost of all or any part of the seeds or manure used on the land is borne by a landowner, and it is not counter balanced by either the receipt by him of a large share of the produce or by any other means;
- (c) where a landowner provides at his own cost, improved agricultural implements for the use of his tenants, and makes no charge for the use thereof, whether by way of large share or the produce or otherwise;
- (d) where a landowner takes no share of fodder or receives nothing on account thereof and permits a tenant—
 - (i) to devote a specified area per pair of bullocks or some similar unit of area to the raising of fodder crops;
 - (ii) to cut certain crops for green fodder; or
 - (iii) to use his land or a part thereof or growing fodder in any other manner;
- (e) where a landowner employs paid agency at his own expenses to collect his share of produce;
- (f) where a landowner advances money free of interest of his tenants for agricultural purposes;

Provided that the rate of interest to be allowed in making such deductions shall not be lower than that allowed by the nearest branch of the State Co-operative Bank on the deposits made with it, or higher than the one charged on the loans advanced by it.

7. *Conversion of estimates from produce to moeny value and prices to be adopted in the process.*—(1) The estimates of produce shall then be converted into money value. The prices to be adopted for conversion shall be the average prices which are likely to be obtained for their crops by the agriculturists during the coming settlement, but shall be based on the average of a sufficiently long period in the past and it shall be assumed that the range of future prices shall not be dissimilar. The prices prevailing in years of famine or severe scarcity shall be excluded from the calculations.

(2) The prices adopted for each crop shall further be based on the prices current in the month in which the agriculturists of the tract ordinarily dispose of their produce. If in any estate or estates concerned, it is found that most of the agriculturists take their produce to market towns and dispose of there, an allowance shall be made for the cost of cartage to markets and for any fees paid at markets to agents, weighmen, etc., and for any other customary deductions, as may, actually be prevailing.

Note.—In determining the prices to be adopted, the Revenue Officer shall scrutinise, among other data available, the following:—

- (a) shop-keepers' books in selected villages;
- (b) harvest prices for each assessment circles reported by the Field Kanungo for entry in the circle note books;
- (c) harvest prices published in Gazette;
- (d) prices obtaining in the markets; and
- (e) prices obtained by big landowners for their produce.

8. *Estimates of net assets based on cash rents.*—A second estimate of net assets shall also be framed on the basis of cash rents payable by tenants, prevailing in the estate or estates concerned, on the assumption made in clause (12) of section 4. This estimate shall only be framed where the following factors are present:—

- (a) the existence in any circle, of a system of cash rents on a sufficiently large scale to enable them to be used as a guide in estimating the rent value of the remainder of the land of the circle; and
- (b) the recognition in the revenue records of such distinctions of soil and class as are usually accompanied by marked difference of rented value.

9. *Abnormal rents.*—(1) All rents which are not true economic rents, and are not based on the prevailing rent rate or the average rate actually paid on any class of land, shall be excluded by the Revenue Officer from his calculations as abnormal. For that purpose the following rent shall be considered abnormal:—

- (a) rents consisting of the land revenue, with or without a small additional payment as proprietary fee, unless the land revenue is high and the land is poor;
- (b) privileged rent paid by relations, friends, dependents or persons discharging religious duties; and
- (c) rents unduly inflated by jealousy or special local or personal conditions of a transitory character i.e. rents so exorbitant as to be no index of the real letting value of land and rents in which other factors such as mortgage money enter.

(2) The Revenue Officer shall scrutinise cash rents if any, carefully in each village as it comes under inspection. He shall satisfy himself that they have been correctly recorded, and shall then decide what rent shall be eliminated as abnormal.

10. *Estimates of net assets.*—The Revenue Officer shall, from the rents remaining after elimination of abnormal rents, frame an estimate of landowner's net assets, on the following guidelines:—

- (i) the provisions of the rule 6 shall *mutatis mutandis* apply;
- (ii) deductions shall be made, if necessary, for fallows or bad harvests:

Provided that the amount of the deduction to be made in each case shall be based on the result of the local enquiries made by the Revenue Officer;

- (iii) deduction shall be made for shortage in collection of rent where such shortage is not due to bad management.

11. *Miscellaneous income.*—Should the landowners, whether they take rents in cash or in kind, also enjoy as such, any income or dues from lands which have not been taken into account in the estimates framed under this chapter, the amount of such income or dues shall be added to the net assets.

12. *Estimates of true net assets.*—The final estimates of net assets calculated in accordance with this chapter, shall be compared, and the Revenue Officer shall then arrive at a definite estimate of what are the true net assets of each estate/estates concerned.

CHAPTER III

ASSESSMENT OF LAND REVENUE

13. *forecast report*.—(1) Before the assessment of any area is undertaken a forecast report shall be submitted, of the expected financial results of the assessment, showing whether, for the fiscal reasons or otherwise, reassessment is desirable. In the report specific mention shall be made, *inter alia*, of the following matters:—

- (a) the existing assessment, the suitability of its form to local circumstances and the fairness of its distribution over estates;
- (b) changes in cultivation, population, means of irrigation and markets and communications;
- (c) rainfall;
- (d) prices; and
- (e) any other factor affecting the general property of the tract.

(2) Before the report is prepared, the leading agriculturists and organisations of landowners of the area concerned shall so far as practicable, be consulted, and a mention of it shall be made in the report indicating what opinions have been expressed by them and the reaction of the Revenue Officer concerned thereupon.

14. *Publication of proposals*.—(1) The Revenue Officer shall frame his proposals with respect to assessment circles, classes of soil, selected year and prices to be adopted in accordance with the provisions of rules 3, 4, 5 and 7 as soon as possible after the commencement of settlement operations.

(2) The Revenue Officer shall have an abstract of his proposals prepared in Hindi in Devanagiri script. This abstract shall be got published in the Himachal Pradesh Government Gazette. Printed copies of this abstract shall be supplied by post to all Legislators, Organisations of landowners, Pradhans of Gram Panchayats, Lambardars, Non-official Members of the Panchayat Samitis and Zila Parishads, representing the area concerned for inviting their objections or suggestions. A period of thirty days from the date of posting shall be allowed within which they may file objections or send suggestions on all or any of the matters referred to in sub-rule (1) with or to the Revenue Officer.

(3) The Revenue Officer shall take such objections etc., into consideration and forward them with his views thereon, together with his proposals, through the Financial Commissioner for the orders of the State Government.

15. *Inspection of estates*.—Before preparing the report prescribed under sub-section (1) of section 54 of the Revenue Officer shall make a special inspection of each estate, and record an inspection note thereon.

16. *Draft assessment report*.—On receipt of the orders of the State Government the Revenue Officer shall, after taking into consideration the existing assessment, the true net assets arrived at under rule 12 and all other relevant factors, prepare a draft report, containing his proposals as to the future assessment of each assessment circle. This report shall contain, *inter alia*, proposals with regard to the following points in respect of each assessment circle:—

- (a) the value of the true net assets calculated by him;
- (b) the reassessment which he proposes; and
- (c) the detailed rates by which he proposes to distribute it over different classes of land or crops.

17. *Abstract of a assessment report to be published*—After the preparation of the draft report, the Revenue Officer shall have a brief abstract prepared in Hindi, in Devnagri script, containing—

- (a) the principal date on which the true net assets estimate has been based, viz., rates of yield assumed rates of rents in cash or kind, average total areas cultivated and matured, deductions allowed or expenses of cultivation, menial's dues, etc., and the value of land as disclosed by sales and mortgages;
- (b) the general considerations on which the pitch and amount of total actual assessment proposed to be taken are based i.e., the increase in resources through irrigation, extension of cultivation, rise in prices, miscellaneous income etc.; and
- (c) the total assessment and the average revenue rates proposed for adoption in framing village assessments, with such brief explanations as may be necessary, including the clear provision that there is no guarantee that any particular estate will be ultimately assessed at the exact rates proposed and get it published in the Government Gazette.

(2) Copies of this abstract shall also be supplied by post to all Legislators, Pradhans of Gram Panchayats, Lambardars, Organisations of Landowners and non-official members of Panchayat Samitis and Zila Parishads representing the area concerned.

(3) A period of thirty days from the date of posting shall be allowed within which any revenue-payer or group of revenue-payers or tenants may make suggestions or objections to the proposed assessment to the Revenue Officer.

(4) All such suggestions or objections etc., shall be considered by the Revenue Officer before preparing a final report.

18. *Final report*.—The Revenue Officer shall then prepare a final report in the light of the suggestions or objections, if any, received and forward it to the State Government, through the Financial Commissioner, for sanction as contemplated under sub-section (2) of section 53, together with:—

- (a) a gist of suggestions or objections, if any received, with his views thereupon, duly supported by reasons for agreement or disagreement, as the case may be, and
- (b) a copy of the draft report prepared under rule 16, together with the abstract as published under rule 17.

19. *Approval of the State Government*.—The report shall be considered by the State Government and after such consideration, it may approve the assessment proposals with deviations within a margin of 3 per cent either way, or without it.

20. *Assessment of particular estates*.—Subject to the provisions of sub-section (3) of section 54, assessment of the each estate shall be fixed according to circumstances.

21. *Progressive assessments*.—Large enhancements of land revenue on particular estates shall, if necessary, be mitigated by the imposition of a revised demand in a progressive form i.e., a portion of the increased demand shall be deferred for a period of 5 to 10 years.

22. *Distribution of a assessment over holdings*.—(1) Before making or revising the distribution of a fixed assessment over the several holdings of an estate, the Revenue Officer shall enquire into the usage followed in the previous distribution and in deciding the method of the new distribution, he shall have regard to that usage and to the wishes of the landowners, so far as may be practicable and equitable.

(2) (a) The Revenue Officer shall then make an order setting forth the method of the former distribution and the method by which the new distribution, is to be made, and shall direct that a

record of the new distribution be prepared, showing,

- (1) serial number of holding;
- (2) landowner (with description) liable for the land revenue on holding;
- (3) area of holding, with such details as are necessary for the purpose of distribution;
- (4) rate of measure by which the new distribution is made;
- (5) amount charged to each holding by former distribution;
- (6) rates and cesses charged by a percentage on the land revenue payable by each holding by the former distribution;
- (7) amount charged to each holding by the new distribution; and
- (8) rates and cesses charged by a percentage on the land revenue payable by each holding by the new distribution.

(b) Where the rent of tenancy is the whole or a share of the land revenue thereof with or without an addition in money, kind or service, the tenancy and the result of proceedings, if any, taken under section 21 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (8 of 1974) shall be shown in this record under the landowner's holding of which the tenancy is part by an additional entry showing the tenant's name being inserted between entries (2) and (3).

(3) The record thus made shall be given publicity delivering a copy thereof to the headman of the estate, and by pasting another copy at a conspicuous place in or near the estate. A copy shall also be supplied to the patwari.

(4) If the assessment is in the form of rates chargeable according to the result of each year or harvest, the Assistant Collector, to whom the Revenue Officer may assign this business by order under sub-section (1) of section 12, shall cause a record of the sum chargeable to each holding to be prepared for each year or harvest, as the case may be, giving the particulars set out in sub-rule (2) [entries (5) and (6) expected], and shall give publicity of it in the manner prescribed in sub-rule (3).

CHAPTER IV

PRINCIPLES FOR ALLOWING EXEMPTION FROM ASSESSMENT FOR IMPROVEMENTS

23. Exemption of land benefited by improvement from enhancement.—(1) When a Masonary well is constructed at private expense or with the aid of loan from Government, for purposes of irrigation, after the coming into force of these rules, the land which benefits from the well shall be exempted from liability to any such enhanced or additional assessment of land revenue until the expiry of such period as may have been sanctioned at previous settlement, reckoned from the harvest in which the well is first brought into use. The minimum period of exemption for the purpose of this rule shall be 20 years, but in any case where it is shown that such period is insufficient to repay the landowner twice the cost of the well out of the additional net assets due to the well, it may be extended to such longer period, not exceeding 40 years, as may be considered sufficient for that purpose. In case where the Revenue Officer refuses to grant an exemption upto a period of 40 years, the aggrieved party shall have a right of appeal to the Financial Commissioner.

(2) When a well, whether in use or out of use through disrepair, is repaired for the purpose of irrigation, an exemption from liability similar to that in sub-rule (1) may be given for such period, if any, not exceeding half the period specified in that sub-rule, as the officer granting the exemption may consider equitable, with reference to the amount of expenditure incurred on repairing the well and the principles laid in sub-rule (1).

(3) When a tube-well is constructed at private expense or with the aid of loan from Government for purposes of irrigation the land which benefits from the well shall be exempted from

liability to any enhanced or additional assessment of revenue as may be due to the existence of the well until the expiry of such period as may be considered by the Financial Commissioner to be sufficient to repay the landowner twice the cost of the well out of the additional net assets due to the existence of the well. The minimum period of exemption for the purpose of this rule shall be 30 years and the maximum 40 years.

(4) During the period of exemption specified in sub-rules (1) to (3) the land revenue assessment of the land irrigated by the well or tube-well shall not exceed the amount which could have been assessed, had no new well been constructed or no old well repaired, and in particular no fixed lumpsum assessment shall be imposed on the well during the period of exemption.

(5) In tracts where there is practically no assessment on land due its un-irrigated aspect, the whole fixed assessment on well irrigated lands lying beyond the reach of river floods or canal water i.e. chahi-khalis shall be remitted during the period of exemption. In the case of chahi sailab, chahi-nahri lands, the rates of assessment imposed for the period of exemption shall be as follows:—

- (a) where the land irrigated by the well is situated within reach of river floods, the sailab rate or rates, fixed or fluctuating, as the case may be, as sanctioned for the time being; and
- (b) where it is within reach of canal water, the nahri-khalis rate or rates, fixed or fluctuating, as the case may be, as sanctioned for the time being:

Provided that where in the tracts mentioned above, there is no fixed assessment on well-irrigated lands, no rates other than sailab or nahri-khalis rates, as above, shall be charged.

(6) For irrigation works other than wells or tube-wells, such as dams, reservoirs, water-cuts, minor canals or canal distributaries constructed or repaired at private expense or with the aid of a loan from Government, exemptions similar to those allowed for wells under sub-rules (1) and (2) shall be granted. The period of such exemptions shall be determined in each case by the Revenue Officer, but no exemption for a period exceeding 10 years shall be granted without the sanction of the Financial Commissioner, or exceeding 20 years without that of the State Government.

(7) The periods of exemption specified in the foregoing sub-rules may, for sufficient reason, be extended with the sanction of the State Government.

24. Remission of revenue when wells fall out of use.—(1) A remission of so much of the assessment of the land irrigated from a masonry well or tube-well shall be granted as is based on the profits of irrigation from such well when,—

- (a) the well ceases to be fit for use; or
- (b) irrigation from it is superseded by canal irrigation and canal-advantage revenue or owner's rate has been imposed.

(2) A similar remission may be granted if the well, though still fit for use, has been out of use for four harvests:

Provided that no remission shall be given if the disuse of the well—

- (a) occurs in the ordinary course or husbandry, the well being intended for use merely in seasons of drought; and
- (b) is due to the introduction of canal irrigation and canal advantage revenue or owner's rate has been imposed.

Explanation.—The revenue based on the profits of irrigation from the well shall ordinarily be assumed to—

- (i) where a lump sum has been imposed at the distribution of assessment on the well in addition to a non-well rate, such lump sum;

- (ii) where a lump sum, inclusive of non-well rate, has been imposed at the distribution of assessment such lump sum after deducting the equivalent of non-well rate; and
- (iii) where the distribution of the assessment has been by soil rates, the difference between the actual assessment of the area irrigated and the amount which would have been assessed on that area if it had not been irrigated.

25. *Period of exemption for wells to be fixed at settlement.*—When settlement operation are in progress, the Revenue Officer shall obtain, through the Financial Commissioner the sanction of State Government with respect to the period of exemption for wells, other than tubewell, for each assessment circle.

26. *Grant of exemption certificates at settlement.*—In every case in which the Revenue Officer grants exemption, he shall give the landowner a certificate specifying the well or other work on account of which it is granted; the rate of its construction or repair; the term for which the exemption will last; the land which would otherwise have been assessed at irrigated rates and the additional demand to be imposed at the end of the period of exemption. If the land is under fluctuating assessment, the certificate shall further state what the exemptions will be under the system as sanctioned for the tract.

27. *Grant of certificate at other times.*—When a well, tube-well or other work is constructed or repaired during the currency of a settlement in such circumstances as to entitle the owner to an exemption from assessment at irrigated rates, the Revenue Officer shall make a special enquiry and grant a certificate of exemption in accordance with the provisions of rule 23. If the exemption is to take effect immediately, the certificate shall state, as nearly as may be, all the particulars mentioned in rule 26, and in addition shall show distinctly the amount of existing land revenue to be remitted. But, if the exemption is not to take effect till the next revision of assessment, no action need to be taken unless the owner of the work in question applies for a certificate. In such a case, no entry shall be made as to the area subject to the concession or the amount of the exemption.

28. *Exemption of reclaimed waste lands.*—(1) When a landowner desires to secure an exemption from assessment on reclaimed waste land in order to compensate him for incurring substantial expenditure on its reclamation, he shall apply, before he commences the work, to the State Government for such exemption, giving a description of the land to be reclaimed, the difficulties attending its reclamation and the sum proposed to be expended on reclamation operations. The State Government, shall, after making such enquiries as it deems necessary, decided as to whether any exemption be given.

(2) If the exemption applied for is sanctioned, the maximum period of the exemption shall be fixed at the close of reclamation operations. The State Government after verification of the actual amount expended on reclamation and the area reclaimed, shall, by written order, exempt the area reclaimed from assessment of land revenue for a period sufficient to re-imburse the landowner to the extent of twice the sum expended on the reclamation operations, subject to the maximum limit previously fixed.

CHAPTER V

MANNER OF ANNOUNCEMENT OF ASSESSMENT

29. *Order of assessment for each estate.*—The Revenue Officer shall, on receipt of the order of Government on his assessment proposals, draw up an order determining the assessment proper on each estate.

30. *Announcement of assessment.*—(1) For the purpose of announcing the assessment imposed on such estate, a notice shall be issued summoning the headmen and other persons

interested to attend at a place and on a date specified. On such date and at such place the Revenue Officer shall announce the assessment.

(2) The headmen of each estate shall be given a memorandum showing the future assessment of the estate, and any additional particulars deemed necessary.

(3) The harvest from which the new demand shall take effect shall be announced to the headmen and other persons interested, and shall be noted in the memorandum furnished to the headmen.

CHAPTER VI

THE MANNER OF CALCULATION OF THE RATE OF LAND REVENUE

31. *Calculation of incidence.*—(1) In assessment circles in which fixed assessment was imposed at the last previous assessment, the rate of incidence of such assessment shall be the rate obtained by dividing the total assessment on cultivated land, as finally imposed by the Revenue Officer who made the assessment, by the cultivated area as ascertained by him for the purposes of assessment.

(2) In assessment circles in which fluctuating assessment was imposed at the last previous assessment, the average of crops forming the basis of the net assets at such assessment shall be multiplied by the final rates sanctioned. The figures thus arrived at shall be divided by the cultivated area as ascertained for the purpose of assessment, by the Revenue Officer, who imposed the assessment, and the result shall be the rate of the last previous assessment.

(3) In assessment circles in which the assessment imposed at the last previous assessment was partly fixed and partly fluctuating, the average acreage of crops forming either partly or wholly, the basis of the net assets, estimate of such assessment that are subject to assessment, shall be multiplied by the final rates sanctioned for fluctuating assessment. To the figures thus arrived at, shall be added the final fixed demand imposed by the Revenue Officer, and the total shall be divided by the cultivated area as ascertained for the purpose of assessment by the Revenue Officer. The result shall be the rate of incidence of the last previous assessment.

(4) The rate of incidence on the cultivated area for the purpose of the revised assessment shall be determined *mutatis mutandis* by such of the methods in sub-rules (1), (2) and (3) of this rule as are applicable to the circumstances of the circles under assessment applied to the cultivated area determined by the Revenue Officer at re-assessment.

32. *Repeal and Savings.*—(1) The Punjab Land Revenue Assessment Rules, 1929 as applicable and in force in the State of Himachal Pradesh are hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the rules referred to in sub-rule (1) anything done, any action taken, notification, proclamation, order or directions issued or notification schemes framed under the repealed rules shall be deemed to have been done or taken, issued, made or framed, as the case may be, under the corresponding provisions of these rules, if any, and shall continue to be in force until directed otherwise or superseded, by anything done or any action taken by the competent authority.

